

फलिसितीन में यहूदी राष्ट्र-राज्य पर गांधी का रुख

प्रलम्ब के लिये:

[महात्मा गांधी, इजरायल-फलिसितीन संघर्ष, बालफोर घोषणा](#)

मेन्स के लिये:

भारत के हितों पर देशों की नीतियों और राजनीतिका प्रभाव, इजरायल-फलिसितीन संघर्ष को लेकर भारत का रुख और प्रस्तावति समाधान

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

[महात्मा गांधी](#) फलिसितीन में यहूदी राष्ट्र-राज्य की स्थापना का वचिरकि रूप से वरिध करते थे, [इजरायल और फलिसितीन के बीच चल रहे संघर्ष](#) एवं तनाव के संदर्भ में उनके वचिर काफी चर्चा में है।

गांधी द्वारा फलिसितीन में यहूदी राष्ट्र-राज्य के वरिध का कारण:

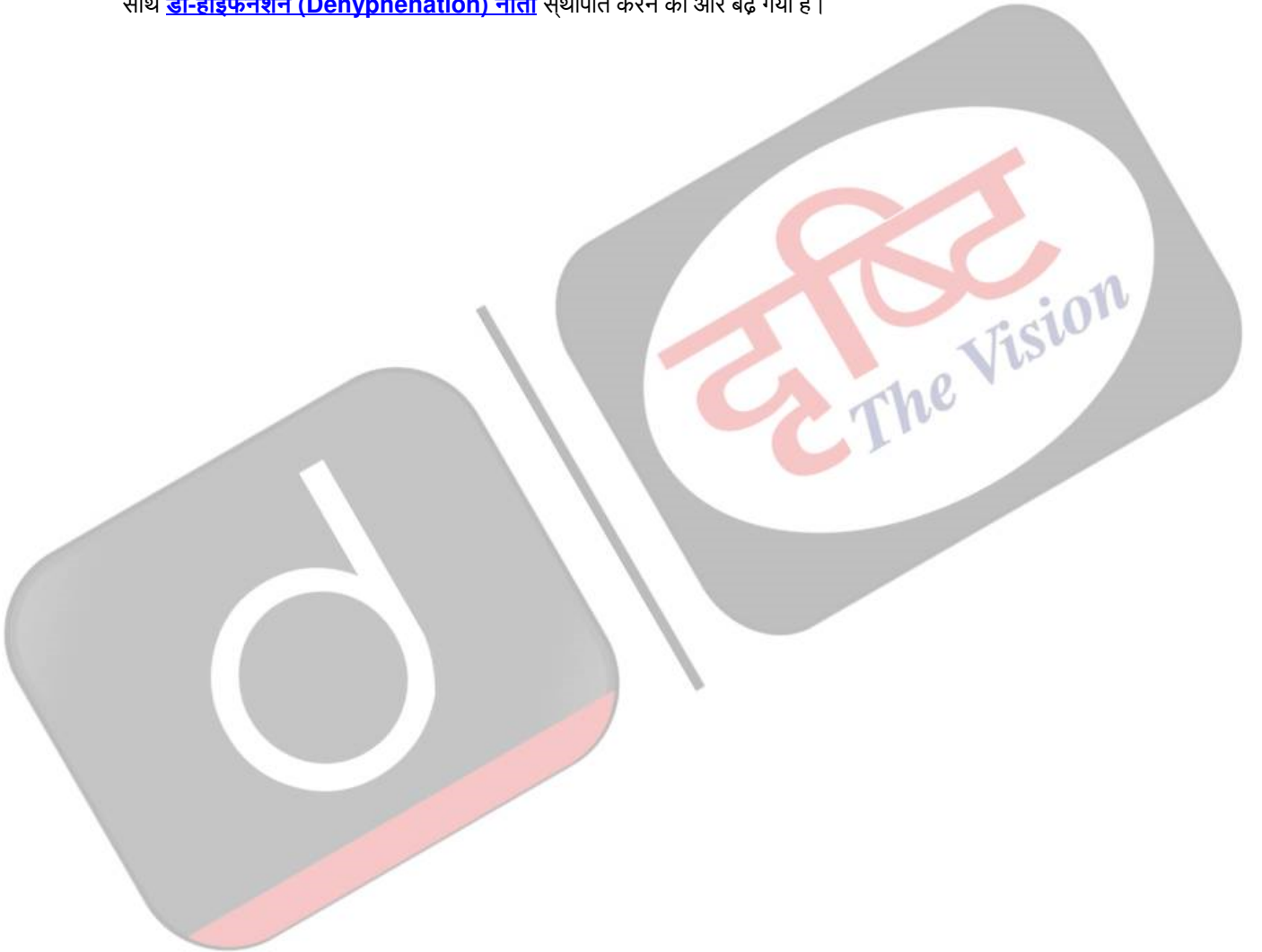
- यूरोप में यहूदी लोगों की दुर्दशा:
 - 1930 और 1940 के दशक में एडॉल्फ हटिलर के नेतृत्व वाले नाज़ी शासन के तहत यूरोप में यहूदियों को अत्यधिक उत्पीड़न एवं भेदभाव का सामना करना पड़ा।
 - नाज़ियों के शासन के दौरान व्यवस्थित रूप से लगभग छह मिलियन यहूदियों का नरसंहार किया गया, उन्हें नज़रबंदी शिविरों में रहने या नरिवासति होने को मज़बूर होना पड़ा।
- यहूदियों के प्रति गांधी की सहानुभूति:
 - गांधीजी को यहूदी लोगों के प्रति अपार सहानुभूति थी, इन लोगों को ऐतिहासिक रूप से उनके धर्म के कारण प्रताड़ित किया गया था।
 - गांधीजी ने पाया कि यूरोप में यहूदियों और भारत में अफ़ूतों के साथ होने वाले व्यवहार में काफी समानताएँ हैं तथा उन्होंने दोनों समुदायों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार की काफी आलोचनाएँ भी कीं।
 - गांधी जर्मनी द्वारा यहूदियों के उत्पीड़न को लेकर बहुत चिंतित थे और उनका मानना था कि इस तरह के उत्पीड़न को रोकने के लिये अगर जर्मनी के साथ युद्ध करना पड़े तो यह उचित होगा।
- ज़ायोनी आंदोलन और उसके लक्ष्य:
 - 19वीं सदी के अंत में फलिसितीन में यहूदी लोगों के लिये एक राष्ट्रीय मातृभूमि की स्थापना के लक्ष्य के साथ ज़ायोनी आंदोलन की शुरुआत हुई।
 - [प्रथम विश्व युद्ध](#) के बाद इस आंदोलन को और बल मिला, साथ ही इसे वर्ष 1917 की [बालफोर घोषणा](#) (जसिके द्वारा फलिसितीन में एक यहूदी राष्ट्र-राज्य की स्थापना हेतु समर्थन दिया गया था) का प्रोत्साहन भी प्राप्त हुआ।
 - [द्वितीय विश्व युद्ध](#) के बाद वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फलिसितीन को अलग-अलग यहूदी और अरब राज्यों में वभाजति करने वाली एक [वभाजन योजना](#) का प्रस्ताव रखा, जसिके अनुसार यरुशलम एक अंतरराष्ट्रीय शहर होगा।
 - यहूदी नेताओं ने इस योजना को स्वीकार कर लिया किंतु अरब द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया, जसिसे हिसा भड़की।
 - 14 मई, 1948 को इजरायल को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया।
- यहूदी राष्ट्र-राज्य के प्रति गांधी का वरिध:
 - गांधीजी ने फलिसितीन में यहूदी राष्ट्र-राज्य को गलत और अमानवीय मानते हुए इसका वरिध किया। उनका मानना था कि यहूदी मातृभूमि की स्थापना के लिये मूल अरब आबादी को वसिथापति करना मानवता के खिलाफ अपराध कृत्य होगा।
 - गांधीजी को लगा कि यहूदी केवल "अरबों की सद्भावना से" फलिसितीन में बस सकते हैं और इसके लिये उन्हें "ब्रिटिशों के साथ जुड़ाव को कम करना होगा"।
 - उनका मानना था कि कोई भी धार्मिक कृत्य, जैसे यहूदियों का फलिसितीन लौटना, गंभीरता से नहीं बल्कि अरबों की सद्भावना के साथ लागू होना चाहिये।
 - गांधी का मानना था कि फलिसितीन में यहूदी मातृभूमि की अवधारणा दुनिया भर में यहूदी अधिकारों की लड़ाई का खंडन करती है। उन्होंने

सवाल कया कथिदफलिस्तिनी यहूदयिों का एकमात्र घर है तो क्या वे दुनिया के उन हस्सिों को छोडेंगे, जहाँ पर वे पहले से बसे हुए हैं।

गांधी के रुख का भारत की इज़राइल-फलिस्तिनी नीतपर प्रभाव:

- गांधीजी की राय और उनके स्वयं के साम्राज्यवाद-वरीध का भारत के पहले प्रधानमंत्री [जवाहरलाल नेहरु](#) पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे दशकों तक उभरते राष्ट्र की वदिश नीतको आकार देने के लयि ज़मिमेदार थे, जसिके कारण भारत ने फलिस्तिनी को वभिाजति करने वाले संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 181 के खलिाफ वोट कयि।
- 17 सतिंबर 1950 को, भारत ने आधिकारिक तौर पर इज़राइल राज्य को मान्यता दी, लेकनि प्रधानमंत्री पी.वी. नरसमिहा राव के द्वारा वर्ष 1992 में आधिकारिक राजनयिक संबंध स्थापति कयि।
- भारत, **फलिस्तिनी मुक्त संगठन (PLO)** को एकमात्र फलिस्तिनी प्रतिनिधिके रूप में स्वीकार करने वाले पहले गैर-अरब देशों में से एक था। वर्ष 1988 में भारत ने फलिस्तिनी को एक राज्य के रूप में मान्यता दी।
- हालाँकसमय के साथ भारत की नीत में भी कुछ बदलाव आए, जो उसके रणनीतिक और आर्थिक हतिों को दर्शाते हैं।
 - हाल ही में भारत इज़राइल और फलिस्तिनी दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलति करते हुए [दो-राज्य समाधान](#) या 'टू स्टेट सॉल्यूशन' (**Two-State Solution**) को प्राथमकित्ता देने और शांतपूरण तरीके से दोनों देशों के लयि आत्मनरिणय के अधिकार के साथ [डी-हाइफनेशन \(Dehyphenation\) नीत](#) स्थापति करने की ओर बढ़ गया है।

//



इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष

इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष, मध्य पूर्व में क्षेत्र और आत्मनिर्णय पर एक लंबे समय से चला आ रहा भूराजनीतिक विवाद है।

शुरुआत

- संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1947 में प्रस्ताव 181- विभाजन योजना का अंगीकरण किया
- वर्ष 1948 में इजराइल राज्य का निर्माण हुआ, जिससे पहले अरब-इजरायल युद्ध की शुरुआत हुई (इजराइल को जीत हासिल हुई)
- फिलिस्तीनी विस्थापित हुए
- क्षेत्र का विभाजन- इजराइल राज्य, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी

प्रारंभिक तनाव और संघर्ष (1956-1979)

- स्वेज संकट और वर्ष 1956 में सिनाई प्रायद्वीप पर इजरायली आक्रमण
- छह दिवसीय युद्ध (वर्ष 1967)- इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, पूर्वी येरुशलम और गोलन हाइट्स पर नियंत्रण हासिल कर लिया।

जेरुसलम के राजधानी बनाने पर विवाद

- इजराइल का दृष्टिकोण: पूर्ण और एकजुट येरुशलम
- फिलिस्तीनियों का दृष्टिकोण: पूर्वी येरुशलम भविष्य की राजधानी

- यूम किप्पुर युद्ध (1973)- मिस्र और सीरिया द्वारा आश्चर्यजनक हमला
- कैंप डेविड एकाडर्स (1979) मिस्र और इजराइल के बीच

इतिफादा (अरबी में 'हिला देना')

- पहला इतिफादा- वर्ष 1987 से 1993 तक
 - हमास (वर्ष 1987)- एक फिलिस्तीनी राजनीतिक दल जिसे अमेरिका द्वारा एक विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया था, की स्थापना का नेतृत्व किया
 - प्रतिक्रिया- मैड्रिड सम्मेलन, 1991 (अमेरिका और रूस की अध्यक्षता में)
- दूसरा इतिफादा- वर्ष 2000-2005
- नवीनतम वृद्धि (वर्ष 2023) को "तीसरी इतिफादा" की शुरुआत कहा जा रहा है

ओस्लो समझौता (अमेरिका द्वारा मध्यस्थता)

- प्रथम (1993)
 - वेस्ट बैंक और गाजा में फिलिस्तीनी स्वशासन के लिये ESTD ढाँचा
 - इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पारस्परिक मान्यता को सक्षम बनाया गया

दूसरा (1995)

- ओस्लो I समझौते पर विस्तारित
- वेस्ट बैंक के कई शहरों और कस्बों से इजराइल की पूर्ण वापसी अनिवार्य है

वर्ष 2000 के बाद का संघर्ष और प्रतिक्रियाएँ

- 2013- अमेरिका के नेतृत्व में शांति प्रक्रिया शुरू हुई
- 2014-18- गाजा संघर्ष (2014)
 - फिलिस्तीन ने ओस्लो समझौते (2015) के तहत क्षेत्रीय विभाजन से अलग होने की घोषणा की
- 2018-20- अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) के तहत फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिये फंडिंग रद्द कर दी
 - अमेरिका ने "शांति से समृद्धि" योजना का प्रस्ताव रखा
- 2020: अब्राहम समझौता
- 2022-2023:
 - इजराइल ने जेनिन शरणार्थी शिविर पर किया हमला
 - हमास ने "ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड" लॉन्च किया तथा इजराइल ने "ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स" लॉन्च किया (दोनों वर्ष 2023 में)
 - इजराइल ने युद्ध की स्थिति घोषित कर दी
 - भारत का रुख:
 - इजराइल और फिलिस्तीन के लिये दो राज्य समाधान का समर्थन करता है
 - हाल ही में इजराइल पर हमास के हमले की निंदा की



UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2023)

कथन-I: इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयकि संबंध स्थापति कयि है।

कथन-II: 'अरब शांति पहल' सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग द्वारा हस्ताक्षरति हुआ।

उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

- (a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तब कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है।
- (b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।
- (c) कथन-I सही है कति कथन-II गलत है।
- (d) कथन-I गलत है कति कथन-II सही है।

उत्तर: (c)

प्रश्न. कभी-कभी समाचारों में "टू स्टेट सॉल्यूशन" शब्द का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? (2018)

- (a) चीन
- (b) इजरायल
- (c) इराक
- (d) यमन

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. 'आवश्यकता से कम नगदी, अत्यधिक राजनीति ने यूनेस्को को जीवन- रक्षण की स्थिति में पहुँचा दिया है।' अमेरिका द्वारा सदस्यता परित्याग करने और सांस्कृतिक संस्था पर 'इजरायल वरिधी पूर्वाग्रह' होने का दोषारोपण करने के प्रकाश में इस कथन की वविचना कीजिये।' (2019)

प्रश्न. "भारत के इजरायल के साथ संबंधों ने हाल ही में एक ऐसी गहराई और वविधिता हासिल की है, जिसकी पुनर्वापसी नहीं की जा सकती है।" वविचना कीजिये। (2018)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/gandhi-s-stance-on-jewish-nation-state-in-palestine>

